बीपीएल के लिए गठित होगा आयोग

चुनाव आयोग की तर्ज पर करेगा काम

हिन्दुस्तान ब्यूरो
पटना

राज्य में बीपीएल (गरीबी रेखा के नीचे के परिवार) के लिए आयोग का गठन होगा। यह आयोग चुनाव आयोग की तर्ज पर काम करेगा। वोटर लिस्ट की तर्ज पर बीपीएल परिवारों की लिस्ट बनेगी।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण विकास विभाग को आयोग का प्रारूप तैयार करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने जॉबकार्डधारियों के अतिरिक्त राज्य की सभी 9 करोड़ जनता को ई-शक्ति कार्ड उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। खासबात यह होगी कि इस स्मार्ट कार्ड में यूआईडी नंबर भी होगा। यह कार्ड बहुउद्देशीय होगा।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की पांच घंटे तक मैराथन समीक्षा की। समीक्षा बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्र, मुख्य सचिव अनूप मुखर्जी, विकास आयुक्त के.सी.साहा, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव संतोष मैथ्यू, मुख्यमंत्री के सचिव चंचल कुमार और अतीश चंद्रा मौजूद थे।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए और ग्रामीण विकास विभाग को उस दिशा में तत्काल काम शुरू करने को कहा। मनरेगा के तहत कार्यक्रम पदाधिकारियों, पंचायत टेक्नीकल असिस्टेंट, पंचायत रोजगार सेवक और इंजीनियरों के रिक्त पदों को तत्काल भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उनका मानदेय भी बढ़ाया जाएगा। प्रखंडों में पंचायतों की संख्या के आधार पर मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारियों की तैनाती होगी।

मनरेगा की योजनाओं का चयन गांव के लोग करेंगे। ग्रामीण बताएंगे कि उनके गांव में कौन सी योजना शुरू की जाए। इसके लिए वसुधा केन्द्र के माध्यम से भी सुझाव प्राप्त किए जाएंगे। छह माह की तय समय सीमा में इंदिरा आवास बनाने वाले लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। लाभार्थियों की परेशानी दूर करने के लिए पंचायत स्तर पर कैम्प लगाए जाएंगे। उस कैम्प में आवास आवंटन से लेकर बैंक पासबुक तक उपलब्ध कराए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की पांच घंटे तक समीक्षा की

राज्य सरकार का फैसला

- राज्य की 9 करोड़ जनता को यूआईडी नम्बर सहित ई-शक्ति कार्ड
- जॉबकार्डधारियों का घर-घर सर्वे का निर्देश
- भरे जाएंगे मनरेगा के रिक्त पद, बढ़ेगा मानदेय
- मनरेगा की योजनाओं का चयन गांव के लोग करेंगे